भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1536
09 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: विशेष कृषि विकास मिशन

1536. श्री अनुराग शर्माः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बुंदेलखंड क्षेत्र अपनी बार-बार सूखा पड़ना, मृदा क्षरण और जल का अभाव सहित विशिष्ट भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के कारण लगातार गंभीर कृषि चुनौतियों का सामना कर रहा है;
(ख) क्या सरकार ने कृषि स्थिरता में सुधार, उत्पादकता बढ़ाने और क्षेत्र के किसानों की दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समर्पित "बुंदेलखंड विशेष कृषि विकास मिशन" स्थापित करने की आवश्यकता के संबंध में जांच की है;
(ग) यदि हां, तो विचाराधीन किसी परामर्श या प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या प्रस्तावित मिशन में जलवायु अनुकूल फसलें, सूक्ष्म सिंचाई विस्तार, मृदा स्वास्थ्य सुधार, कृषि-वानिकी को बढ़ावा, किसान प्रशिक्षण, मूल्य-संवर्धन इकाइयां और बाजार-सम्बद्ध सहायता जैसी पहल शामिल होंगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार का बुंदेलखंड के झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, बांदा, हमीरपुर और चित्रकूट जिलों में निरंतर कृषि संकट को दूर करने के लिए विशेष निधि आवंटित करने या समयबद्ध कार्य योजना आरम्भ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ) सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र में अपनी विशिष्ट भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के कारण आने वाली विभिन्न कृषि चुनौतियों से अवगत है, जिनमें बार-बार सूखा पड़ना, मिट्टी का क्षरण और जल का अभाव शामिल है तथा सरकार इस क्षेत्र में कृषि सततता में सुधार के लिए कई उपाय कर रही है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार, क्षेत्र में कृषि चुनौतियों का समाधान करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं/परियोजनाएं कार्यान्वित कर रही है:

1. बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत एकीकृत कृषि विकास (सौर बाड़) योजना
2. उत्तर प्रदेश मिलेट पुनरुद्धार योजना
3. वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब योजना
4. आत्मनिर्भर भारत कृषक समन्वित विकास योजना (एफपीओ)
5. यू.पी. दलहन विकास योजना
6. परंपरागत कृषि विकास योजना/प्राकृतिक खेती के लिए राष्ट्रीय मिशन
7. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के झांसी जिले में समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के माध्यम से जल का अभाव और भूमि क्षरण को कम करके सामुदायिक क्षमता का संवर्धन।
8. झांसी जिले में कृषि आजीविका क्षमता को बढ़ाने के लिए भूदृश्य संसाधन संरक्षण (एसएडीपी के तहत 2025-26 में मंजूरी) के कार्य वित्तीय मंजूरी के बाद प्रारंभ किया जाएगा।

(ङ): वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की योजनाओं के अभिसरण द्वारा केंद्रित विकास हेतु बुंदेलखंड के झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, बांदा, हमीरपुर और चित्रकूट जिलों को प्रधानमंत्री-धन धान्य कृषि योजना में शामिल किया गया है।

*****